रखेंगे तो वे अपना रख-मुनाफाखोरी नहीं होगी ऐजुकेशन में, यह साफ लिखा हुआ है। इसके तहत हमने एक कमेटी बनाई है ताकि वह इस बारे में हमें पूरी सिफारिशें दे और उसके बाद हम एक गाइडलाइंस ईश्यू करेंगे।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Thank you very much for constituting a committee.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has just now said that the college fee for higher eduction has been enhanced. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, what steps the Government is contemplating to upgrade the quality of education.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन् वैसे तो यह सवाल इससे उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह फीस से संबंधित है, लेकिन क्वालिटी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ''नेक'' नाम की एक संस्था बनी हुई है जो सब विद्यालयों का परीक्षण करती है और हमने यह तय कर लिया है कि हर विश्वविद्यालय और हर प्रोफेशनल कालेज को एक निश्चित अवधि के अंदर अपना परीक्षण करा लेना पड़ेगा और अगर वह परीक्षण नहीं कराएगा तो उसको सूची से बाहर कर दिया जाएगा।

पशुओं में भुखमरी और कुपोषण

*244. **श्रीमती सरोज दुबे:**††
श्री मूल चन्द मीणा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पशु आंशिक भुखमरी और व्यापक कुपोषण के शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार पशुओं को भुखमरी और कुपोषण से बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) देश में चारे की उपलब्धता की काफी कमी है। यह कमी सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और भी बढ़ जाती है जैसा कि मौजूदा सूखे से अनुभव हुआ है।

(ग) आहार और चारे की कमी को कम करने के लिए निम्न प्रबंध किए हैं:-

---

††सभा में यह प्रश्न श्रीमती सरोज दुबे द्वारा पूछा गया।

(1) भारत सरकार ''आहार और चारा विकास कार्यक्रम के लिए राज्यों को सहायता'' नामक अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के जरिए उनके चारा विकास कार्यक्रम में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति कर रही है जिसके तहत केन्द्रीय सहायता चारा बैंक की स्थापना और भूसा/सेल्यूलोसिक अपशिष्ट के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सहायता क्रमश: 75:25 की पद्धति पर और 100:00 केन्द्र:राज्य की भागीदारी के आधार पर प्रदान की जाती है।

(2) भारत सरकार देश के विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में स्थित चारा फार्मों को चलाती है जिसका उद्देश्य किसानों की मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्ता चारा बीजों में वृद्धि करना है।

(3) सरकार चारा फसलों पर केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। किसानों को निशुल्क वितरण के लिए राज्यों के पशुपालन विभागों और राज्य डेयरी परिसंघों को चारा किटों की आपूर्ति की जाती है।

(4) सूखे के कारण रेलवे द्वारा चारे की मुक्त ढुलाई की सुविधाएं दी गई हैं।

(5) अनिवार्य वस्तु अधिनियम-1955 के तहत राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को यह अधिकार दिए गए हैं कि वे अधिक चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारे के अप्राधिकृत संचयन पर प्रतिबंध और चारा मूल्यों को विनियमित करें।

(6) राज्य द्वारा चलाई जा रही संयुक्त यांत्रीकृत कटाई में भूसा/स्टोवर्स को जलाने को बंद करने की सलाह दी गई है ताकि अधिक मात्रा में चारा उपलब्ध हो सके।

(7) राजस्थान की गोशालाओं को 11.66 करोड़ रुपए की सहायता देने के अतिरिक्त एफ सी आई से 30,000 मी॰ टन गोपशु आहार ग्रेड अनाज की अनुमति दी गई है।

(8) एन सी सी एफ और पी एम आर एफ से सूखा प्रभावित राज्यों की गोशालाओं के लिए 25-25 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

Starvation and mal-nutrition among cattle

†*244. SHRIMATI SAROJ DUBEY:††
SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cattle in our country are victims of partial starvation and extensive mal-nutrition;

---

†Original notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Saroj Dubey.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken by Government for saving the cattle from starvation and mal-nutrition?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) There is an overall shortage in availability of fodder in the country. This shortage aggravates during drought and other natural calamities as experienced in the current drought.

(c) The following arrangements have been made to minimize the feed and fodder scarcity:

(i) The Government of India is supplementing the efforts of State Governments in their fodder development programme through its Centrally Sponsored Scheme-"Assistance to States for Feed and Fodder Development Programme" under which Central assistance is provided for establishment of fodder bank and enrichment of straw/cellulosic waste on the pattern of 75:25 and 100:00 Central: State share basis respectively.

(ii) Government of India operates fodder farms located in different agro-climatic zones in the country with the objective to multiply the quality fodder seeds to cater the demand to the farmers.

(iii) The Government is implementing the Central Minikit Testing Programme on Fodder Crops. Fodder kits are supplied to the State Department of Animal Husbandry and State Dairy Federations for onwards distribution to the farmers free to cost.

(iv) Free transportation facilities for fodder has been given by Railways due to drought.

(v) The Government of Rajasthan and Uttar Pradesh have been delegated power under Essential Commodities Act-1955 to regulate the fodder prices and restriction on unauthorized hoarding of fodder in order to make available more fodder.

(vi) State practicing combined mechanized harvesting, have been advised to stop burning of straw/stovers so that more fodder may be made available.

(vii) 30,000 MT cattle feed grade grain has been allotted from FCI besides Rs. 11.66 crores assistance to the Goshalas to Rajasthan.

(viii) Rs. 25.00 crores each from NCCF and PMRF have been earmarked for the Goshalas of drought affected States.

श्रीमती सरोज दुबे: माननीय सभापति जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बे उपाय बता दिए हैं, लेकिन आज पशुओं की जो दुर्दशा है उसके तहत वे बहुत उचित नहीं हैं क्योंकि चराई भूमि निरंतर कम हाती जा रही है और प्रति एकड़ भूमि में चराई के उच्च दबाव के कारण आज पशु भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। सड़क पर हड्डी के ढांचे के रूप में घूमते हुए, कूड़ेदान में मुंह डालकर प्लास्टिक थैली खाकर मरते हुए, कूड़े के साथ कांच के टुकड़े खाकर मरते हुए जानवर इसका प्रमाण हैं। पशुपालन परिवार की आय में वृद्धि के साथ-साथ कमजोर वर्ग के लोगों की आमदनी के लिए रोजगार का एक जरिया भी है। देश में पशुओं की वर्तमान संख्या लगभग 4500 लाख है, देश के प्राकृतिक संसाधनों से यह बहुत अधिक है। एक अनुमान के अनुसार भारत के भूभाग की अधिकतम क्षमता केवल 500 लाख पशुओं के पोषण की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार पशु पोषण क्षमता और पशुओं की संख्या के इस विशाल अंतर को आप कैसे दूर करेंगे ताकि सभी पशुओं को पोषाहार मिल सके और वे भूखे न तड़पें?

श्री अजित सिंह: माननीय सभापति जी, चारे की कमी है। हरा चारा करीब 60 प्रतिशत कम है और सूखे चारे की करीब 20 प्रतिशत कमी है। हम स्टेट्स को इसके लिए इन्करेज कर रहे हैं कि वे चारा उगाने में कुछ मदद करें। गुजरात में यह स्कीम शुरू की गई थी पिछले सूखे के बाद और इस बार राजस्थान में यह स्कीम शुरू की गई है। चारा उगाने के लिए एक मिनिमम् सपोर्ट प्राइस की भी वे बात कर रहे है और दो हजार प्रति एकड़ वे दे रहे हैं, जो जमीन चारे के लिए शिफ्ट हो रही है। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं कि जो चारा फॉरेस्ट में पैदा होता है, जंगल में पैदा होता है, उसको हम किस तरह पशुओं के लिए ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चारे को कम्पेक्ट करने के लिए, उसको कम्प्रैस करने के लिए, उसमें न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए हमने एक स्कीम प्लानिंग कमीशन को दी है ताकि जो उसकी मशीनरी है, वह उसमें सहायता करे जिससे कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चारा ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फिर धान और दालों के हारवेस्टिंग के बाद जो बच जाता है, पंजाब वगैरह में आज उसको जला दिया जाता है, उसको भी किस तरह हम चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में भी हम प्रदेश सरकारों से बात कर रहे हैं।

श्रीमती सरोज दुबे: माननीय सभापति जी, इसके बावजूद भी चारे की कोई व्यवस्था नहीं है और आपने जो सूखे चारे की बात कही, उस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जिन जगहों पर बार-बार सूखा आता है, सूखा चारा वहां पहुंचा दिया जाता है। सूखा चारा खाकर पशुओं में अंधेपन

की बीमारी हो जाती है क्योंकि उसमें विटामिन ई की कमी रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या सूखे चारे के साथ-साथ विटामिन ई के इंजेक्शन भी आप वहां भिजवाते हैं या नहीं? इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में पशु पोषाहार से संबंधित उत्पादों को बेचने की अनुमति दे दी है? क्या ये विदेशी कम्पनियां नियंत्रित मूल्य पर हमारे पशुओं के लिए पोषाहार उपलब्ध करा पाएंगी?

श्री अजित सिंह: सूखे चारे को एनरिच करने की स्कीम है। वह विटामिन ''ई'' है या कौन सा विटामिन है.....(**व्यवधान**)

श्रीमती सरोज दुबे: अभी तो आप सालों से सूखा चारा भेज रहे हैं और तमाम पशु अंधे हो गए हैं। आप कभी इसका सर्वे तो कराकर देखिए। विटामिन ''ए'' के अभाव में पशु अंधे हो रहे हैं। क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार सब जगह देखिए आप।

श्री सभापति: राजस्थान में तो अंधे नहीं हुए हैं अभी।

श्रीमती सरोज दुबे: सर, हुए हैं। सर, राजस्थान में अंधे हुए हैं। मैं बिना प्रमाण के बात नहीं कह रही हूं।

श्री सभापति: बैठिए आप।

श्रीमती सरोज दुबे: बिना प्रमाण के मैंने बात नहीं कही है।

श्री अजित सिंह: अभी तक हमारे यहां चारे की समस्या की तरफ कोई कंसंट्रेटिड थोड़ी बहुत स्कीम्स थी--लेकिन यह एलोकेशन बहुत कम थी--जिसके कारण मैंने कहा कि अब चारे को कम्पेक्ट किया जाए, उसको एनरिच किया जाए तथा किस तरह पशुओं तक पहुंचाया जाए उसके बारे में बहुत सी स्कीम हैं। जो आप कह रही हैं कि विटामिंस की कमी है, वह जो हम चारे को एनरिच करने की बात कर हैं उसके पीछे यही मकसद है। चारे के बारे में कोई बहुत कम्पनियां हमारे देश में आई नहीं हैं, हमारे देश में भी नहीं है, बाहर की भी नहीं है। यह तो एक बिल्कुल अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर है अभी तक। अभी तक हम कंपेक्ट करने की मशीनों की बात कर रहे हैं। पंजाब में कुछ लोगों ने मशीनरी फेब्रीकेट कर ली है। कोई उसकी मेन्युफेक्चरिंग फेसिलिटी नहीं है। तो यह अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर है। धीरे-धीरे अब यह समस्या उजागर हो रही है। इसकी मदद करने की कोशिश हो रही है।

श्रीमती सरोज दुबे: माननीय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में बताइए।

श्री सभापति: देखिए, नहीं-नहीं। आपको तो बहुत जवाब दे दिया।

श्रीमती सरोज दुबे: लोक सभा में उत्तर दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उत्पाद बेचने की छूट दे दी गई है। इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनको उत्पाद बेचने की छूट दे दी गई है?

श्री सभापति: मीणा जी, बोलिए।

श्रीमती सरोज दुबे: सर, मेरे सवाल का जवाब तो आने दीजिए।

श्री सभापति: आपने दो सवाल कर लिए। अब इनका भी सवाल है और टाइम तो इतना ही है।

श्रीमती सरोज दुबे: उत्तर बिना सवाल पूछने का क्या फायदा है?

श्री सभापति: बिना उत्तर के भी संतोष करना पड़ता है।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, राजस्थान में अब की बार भयंकर अकाल है और 5 करोड़ के करीब पशु प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार से पशुओं के चारे के लिये कितना पैसा मांगा है, कितनी आर्थिक सहायता मांगी है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। दूसरे, राजस्थान में अकाल के कारण और चारे के अभाव के कारण हजारों पशु मर गए हैं और उन पशुओं की क्षतिपूर्ति के लिए क्या केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है?

श्री सभापति: बताइए।

श्री अजित सिंह: राजस्थान का पशुधन के ऊपर ही काम चलता है वहां। तो सूखे में बहुत मदद की गई है। कहिए तो मैं फिर आपको बतला दूं। राजस्थान के लिए चारे को मुफ्त ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हमने चारे के लिए तीन हजार मीट्रिक टन गेहूं और चावल भी मुफ्त दिया है प्रदेश सरकार को। वहां पर चार लाख मिनी किट्स भी बांटे गए हैं। जैसा मैंने कहा कि किस तरह चारा ज्यादा हो उसके लिए भी प्रदेश सरकार से बातचीत हुई है और उन्होंने उसकी स्कीम भी शुरू की है।

श्री मूल चन्द मीणा: उन्होंने कितने पैसे की सहायता मांगी है और कितनी आपने दी है?

श्री अजित सिंह: जैसा मैंने कहा कि गौशालाओं के लिए 25 करोड़ प्रधानमंत्री सहायता कोष से और 25 करोड़ एन०सी०सी०एफ० से दिया गया है। यह सारे देश के लिए दिया गया है।

श्री मूल चन्द मीणा: मैं राजस्थान की पूछ रहा हूं।

श्री अजित सिंह: जहां ज्यादा समस्या है, हम समझते हैं कि जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां पैसा ज्यादा दिया जाएगा। पशुओं के लिए राजस्थान को पहले 12 करोड़ रुपया अलग से दिया जा चुका है।

श्री मूल चन्द मीणा: राजस्थान ने कितना मांगा था?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, यह बतला दें। आपने अभी कहा है कि चारा एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाए। तो क्या आपको जानकारी है कि कई राज्यों ने चारे की निकासी पर प्रतिबंध लगा रखा है?

श्री अजित सिंह: यह प्रतिबंध कोई भी स्टेट बिना केन्द्र की अनुमति के नहीं लगा सकती है। कुछ स्टेट्स ने लगाया था और हमने उनसे कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यह प्रतिबंध उन्होंने वापिस ले लिया।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, 135 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने मांगे थे और 11 करोड़ रुपए दिए हैं।

श्री सभापति: उस दिन अकाल पर डिबेट थी। अगर उस दिन बोलते तो सारा जवाब मिल जाता। उस दिन तो आप थे नहीं।

*245. *[The questioner (Shri Ghulam Nabi Azad) was absent. For answer vide pages* 41-42 *infra].*

MR. CHAIRMAN: Q.No. 246.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Mr. Chairman, Sir, if you permit me, I would like to put this question. I have the authority from Mrs. Shabana Azmi to put this question.

MR. CHAIRMAN: Second round में देखेंगे।

*246. *[The questioners (Shrimati Shabana Azmi and Dr. Prabha Thakur) were absent. For answer vide pages* 39-40 *infra].*

Killing of snakes by Madaris

*247. SHRI R.K. ANAND:††
SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that snakes are caught all over the country and sacrificed in Snake-Mongoose fights by Madaris (road showman);

(b) if so, whether Government have imposed a ban to save both the snakes and mongoose;

(c) if so, the punishment against Madaris indulging in such heinous act;

(d) if not, the reasons therefor; and

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri R.K. Anand.